

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) The Kelkar Committee applied the exclusion criteria on a basket of drugs which was worked out by the Committee on the basis of the WHO list and Supplementary List relevant to Indian requirements.

(d) The requisite information, to the extent available with the Government, is given in the annexed Statement.

Statement

| Sl. No. | Name of the formulation | Bulk Drug Involved | Price (Rs.) | Remarks |
|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | Prolutin Depot Inj. 250mg/ml | Hydroprogesterone Caproate | 21.50 | As per MIMC (Dec. 1989). |
| 2 | Prolutin Depot Inj. 500mg/2ml | Do. | 37.50 | |
| 3 | Docabolin Inj. 1x1ml Amp. | Nandrolone Phenyl propionate | 16.67 | June, 1989 prices. |
| 4 | Durabolin Inj. 1ml Amp. | Do. | 15.00 | |

भारत में तेलशोधक कारखानों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तकनीकी सहायता

1644. श्री अजित जोगी :

श्री सोहन लाल धूसिया :

श्री राम सिंह राठवा :

श्री कपिल वर्मा :

श्रीमती वर्णा वर्मा :

कुमारी आलिया :

श्री राम नरेश यादव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह जवाब की क्षमता करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तेलशोधक कारखानों के लिए विदेशों की बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों से तकनीकी सहायता ली जा रही है ;

(e) and (f) For Non-Scheduled drugs the companies are required to furnish information in Form-2A. The manufacturers of Non-Scheduled drugs are free to revise the prices of formulations based on such drugs. However, Government intervene whenever there is an abnormal price increase. In the case of Docabolin Injections, which are based on bulk drug Nandrolone Phenyl Propionate, the manufacturer of it reduced the price from Rs. 18.00 to Rs. 16.67 after Government intervened in the matter.

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस तकनीकी सहायता से क्या लाभ होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री म. एस. गुणवद वामी) : (क) : (ग) देश की सभी तेल रिफाइनरियों द्वारा केन्द्रित आधार पर यथावश्यक रिटेनर शुल्क का विनिश्चित अमिक घंटा उपशुल्क का भुगतान करके बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों से तकनीकी सहायता लिये जा सकने का प्रस्ताव है। इसमें रिफाइनरियाँ उर्जा संरक्षण, सुरक्षा प्रतिपत्ति के तरीकों में सुधार लाने के लिए प्रचालनों का इष्टतम उपयोग करने और सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए नये उत्पादों को विकसित करने की दिशा में विश्व के किसी भी इलाके में अपनाई जा रही क्रियाविधियों और तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान को अद्यतन रखने में समर्थ हो सकेंगी।